High Powered Commission on Pay Party for Income Tax, Excise and Customs Staff

1731. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) When the recommendations of the High powered Commission on pay parity for the Income Tax, Customs and Excise department staff placed before the Government for consideration;

(b) What are the recommendations made by the High-powered Commission on pay parity;

(c) Whether it is a fact that the recommendations are awaiting clearance of the expenditure department as on date *i.e.* 11.11.1998; and

(d) what is the reasons for the abnormal delay in arriving at the conclusion by the expenditure department?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) No High-powered Commission was set up on pay parity of the Income Tax, Customs and Excise department staff.

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

Complaints against M/s. Okara Agro Industries Ltd.

1732. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to State:

(a) whether Government have received reprsentations/complaints from a large number of investors/depositors against M/s. Okara Agro Industries Limited, New Delhi regarding irregularities, Astoppage of maturity value of their deposite since March, 1998;

(b) if so, what action Government have taken to regulate, control and stop the misuse of investors' money to the extent of nearly rupees three crores collected from nearly 35000 depositors by this company; and

(c) what action Government have taken to regulate, control and stop the misuse of investors' money?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ऋण वसूली प्राधिकरणों में दर्ज किये गये मामले

1733. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार अनुपयोज्य आस्तियां कितनी हैं और बैंकों के कुल ऋण में उनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा बड़े ऋणों की वसूली के लिए बनाये गये ऋण वसूली प्राधिकरण में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उनकी राशियां क्या हैं, इनमे से कितने मामलों का फैसला हुआ तथा इनके माध्यम से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर जनार्दनन): (क) दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार धनराशि एवं प्रतिशत की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार अनुपयोज्य आस्तियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं (नीचे देखिए)

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी को अन्तरित/दायर किए गये 16107 मामलों में से डीआरटी द्वारा 1157.96 करोड़ रुपए के 2271 मामलों पर निर्णय ले लिये गये हैं और 13836 मामले उनके पास लम्बित है। 246.19 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है।

विवरण

मूल्य के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल और निवल अनिस्पादित आस्तियां और 31.3.98 की स्थिति के अनुसार सकल/निवल अग्रिमों का प्रतिशत

(राशि करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	सकल राशि	अनिस्पादित आस्ति	निवल राशि	अनिस्पा० आस्ति निवल अ०का%
इलाहाबाद बैंक	1458.93	23.18	859.86	15.09
आन्ध्रा बैंक	341.30	9.86	93.76	2.92
बैंक आफ बड़ौदा	3129.28	14.63	1290.35	6.60
बैंक आफ इंडिया	2669.00	11.55	1570.00	7.13
बैंक आफ महाराष्ट्र	709.09	17.39	316.57	8.59
केनरा बैंक	3580.81	18.69	1255.29	7.52
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2414.53	20.47	1384.74	12.21
कार्पोरेशन बैंक	341.86	7.60	125.46	2.93
देना बैंक	774.79	13.73	439.43	8.28
इंडियन बैंक	3428.39	38.96	1886.67	26.01
इंडियन ओवरसीज बैंक	1255.00	13.38	543.00	6.26
ओरियंटल बैंक	397.23	6.16	287.15	4.84
पंजाब एंड सिंध बैंक	1038.90	26.79	345.08	10.84
पंजाब नेशनल बैंक	2447.00	14.50	1526.00	9.60
सिंडिकेट बैंक	1185.29	15.31	401.94	5.78
यूको बैंक	1780.30	24.04	705.12	11.14
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1194.73	11.18	787.89	7.66
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1451.00	33.50	415.00	12.10
विजया बैंक	532.95	15.21	276.16	7.50
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग	30130.38	16.88	14440.50	8.87

Funding of Development Activities by Insurance Companies

1734. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has decided to allow private companies to operate in the insurance sector;

(b) whether it is also a fact that Government is also allowing foreign equity participation in such private operations;

(c) if so, the impact on investable resources and tax made available to Government by the LIC and GIC in the last three years for addressing the social, development and infrastructural needs;